नईदुनिया

सुनक सरकार की गलती से लंदन से लौटेंगे कई भारतीय : वीजा में गड़बड़ी फर्जी कंपनियों ने पैसे ऐंठे; अब 4100 नर्सों को भारत वापसी का डर

ब्रिटेन । ब्रिटेन में हजारों भारतीय नर्सों पर देश वापसी का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक सरकार की लापरवाही हैं। ये समस्या फर्जी कंपनियों की वजह से पैदा हुई है, जिन्हें सुनक सरकार ने बिना जांच-पड़ताल किए विदेशों से नर्सों को नौकरी पर रखने की इजाजत दी थी। दरअसल, मोटी रकम लेकर कर्मचारियों का वीजा स्पॉन्सर करने वाली इन कंपनियों की हाल ही में जब प्रशासन ने जांच की तो इनमें से ज्यादातर कंपनियां फर्जी निकलीं। इसके बाद सरकार इन कंपनियों द्वारा लाए गए भारतीय नर्सों पर कार्रवाई कर रही है। इस फैसले का असर 7 हजार से ज्यादा नर्सों पर पड़ेगा। इनमें से सबसे ज्यादा भारत के 4 हजार नर्सें हैं। कार्रवाई की गई नर्सों में से 94 प्रतिशत मामले सरकार द्वारा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कारण सामने आए हैं। सुनक सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे ब्रिटेन गए भारतीय ब्रिटेन में विदेशियों को काम पर रखने के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस की जरूरत होती है। सुनक सरकार पर बिना किसी ठोस जांच सैकड़ों कंपनियों को लाइसेंस देने का आरोप है। सरकार ने 268 कंपनियों को लाइसेंस दिया, जिन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं किया।

लाइसेंस हासिल कर चुकी कई कंपनियां भी फर्जी थीं। कोई गलती न होने के बावजूद दंडित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों की मदद करने वाली एनजीओ 'माइग्रेंट्स एट वर्क' के संस्थापक अके अची के मुताबिक अवसर की तलाश में लाखों रुपए का कर्ज लेकर भारतीय देश छोड़कर यहां आते हैं।

ये वे लोग होते हैं जो तमाम नियम कायदों का पालन कर आते है। उनकी कोई गलती न होने के बावजूद वे दंडित किए जा रहे हैं। पहले लाखों के कर्ज का शिकार हुए और अब सरकार की गलतियों का शिकार हो रहे हैं। केयर वर्कर्स यूनियन की महासचिव क्रिस्टीना मैकेनिया ने कहा कि असहाय श्रमिकों को अधर में छोड़ना गलत है। प्रवासियों ने यहां आने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। 18 लाख रुपए देकर भाई-बहन पहुंचे ब्रिटेन, अब देश वापसी का डर महाराष्ट्र की रहने वाली जैनब कॉन्ट्रैक्टर (22) दो बच्चों की मां हैं। वे और उनके भाई इस्माइल (25) ने वीजा स्पॉन्सर के लिए ब्रिटेन की कंपनी को 18 लाख रुपए दिए थे।

न्यूज ब्रीफ

क्या अमेरिका मजबूत, बहु-धार्मिक, बहु-जातीय लोकतंत्र बना रहेगा, भारतवंशियों से बाइडन की सलाहकार का सवाल

वॉशिंगटन । अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसी को लेकर व्हाइट हाउस की एक शीर्ष अधिकारी ने भारतीय-अमेरिकियों से पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर छह महीने बाद मतदान होने वाला है, ऐसे में असली सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका मजबूत, बहु-जातीय, बहु-धार्मिक लोकतंत्र बना रहेगा। हम सभी अमेरिकी सपने का हिस्सा राष्ट्रपति जो बाइडन की घरेलू नीति सलाहकार नीरा टंडन वार्षिक शिखर सम्मेलन और इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट समारोह में भाग लेने पहुंची थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस साल वास्तविक सवाल, जिसका भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, यह है कि क्या हम एक मजबूत, बहु-जातीय, बहु-धार्मिक लोकतंत्र बने रहेंगे, जहां हम में से कईयों का स्वागत किया जाता है, हम सभी अमेरिकी सपने का हिस्सा हैं, या क्या हम उससे पीछे हटना शुरू कर देंगे। चुनाव में शामिल होना जरूरी उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक जरूरी पल है, न केवल आपकी भागीदारी के लिए, बल्कि आपके नेतृत्व के लिए। चुनाव में शामिल होना जरूरी है। बातचीत करना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चों को ज्यादा अवसर मिलें भारतीय-अमेरिकी नेता ने कहा कि पिछले कई दशकों में उनका अनुभव अवसरों को बढ़ाने का रहा है। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में आभारी हूं कि इस देश ने मेरी प्रगति का स्वागत किया है। मैं उन मुद्दों पर व्हाइट हाउस में काम करने के लिए बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूं, जो भारतीय अमेरिकियों और सभी अमेरिकियों के लिए मायने रखते हैं। यह बहुत बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चों को इस देश में हमसे ज्यादा अवसर मिलें। बहुत सारे लोग राजनीति और नीति से जुड़े हुए इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट का दो दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ।

चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत की तकनीकी सहायता बेहद अहम, बोलीं राष्ट्रमंडल महासचिव

लंदन । राष्ट्रमंडल महासचिव पेट्रीसिया स्कॉटलैंड ने भारत की तकनीकी सहायता की सराहना की। उन्होंने

कहा कि राष्ट्रमंडल के लिए भारत की तकनीकी सहायता बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इससे कई विकासशील देशों को विकास संबंधी चुनौतियों से पार पाने की काफी उम्मीद मिलती है, जिन्हें भारत पहले ही स्वीकार कर चुका है और उनसे आगे निकल चुका है। राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों का 22वां सम्मेलन 56 सदस्यीय संगठन की महासचिव ने यह बयान लंदन में राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों के 22वें सम्मेलन की मेजबानी के दौरान दिया। बता दें, सम्मेलन का विषय समावेशी भविष्य के लिए लचीलापन, समानता और कौशल को बढ़ावा देना था। स्कॉटलैंड ने राष्ट्रमंडल के साथ एक खुले स्रोत तरीके से तकनीकी विकास साझा करने की भारत की इच्छा का स्वागत किया और संगठन के शैक्षिक लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की उम्मीद की। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय मार्लबोरो हाउस मुख्यालय में दो दिवसीय बैठक शुरू हुई। इस दौरान स्कॉटलैंड ने मंत्रियों से शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और जीवनभर सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करने में मदद करने का आह्वान किया।

रूस और चीन हमेशा साथ हैं, बीजिंग की यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति को याद आया 75 साल पुराना गीत

बीजिंग । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर हैं। गाजा और यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति का एक साल के भीतर दूसरी बार चीन का दौरा है। अपने पांचवे कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद पुतिन की यह पहली विदेश यात्रा है। दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन पुतिन ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों की तारीफ की और कहा कि रूसी और चीनी हमेशा साथ हैं। 1940 के दशक का एक गीत किया याद मॉस्को और बीजिंग के बीच संबंधों पर जोर देते हुए रूसी राष्ट्रपति ने इसकी तुलना 1940 के दशक के एक गीत से की। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ और क्रॉस-कल्चरल ईयर की शुरुआत के लिए समर्पित एक संगीत कार्यक्रम से पहले पुतिन ने दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के जारी रहने का विश्वास जताया। रूसी और चीनी हमेशा साथ पुतिन ने कहा, यह कार्यक्रम राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित है।

पीओके में जारी संघर्ष पर अलर्ट हुए शहबाज शरीफ समस्याओं का समाधान खोजने के लिए समिति का किया गठन

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों काफी संघर्ष चल रहा है। इसे लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चिंतित हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके के लोगों की समस्या का समाधान खोजने के लिए एक समिति गठित की है। गौरतलब है कि शहबाज एक दिन के दौरे पर मुजफ्फराबाद गए थे। लोगों ने उनके समक्ष अपनी मांग रखी। हालांकि, इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने दंगा फैलाने और हत्याएं करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शरीफ ने पीओके सरकार की कैबिनेट की एक विशेष बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जल शुल्क और नीलम-झेलम जलविद्युत संयंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करने लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। पीओके में आटे की ऊंची कीमतों और बढ़ें हुए बिजली बिलों और करों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प के दौरान एक पुलिस जवान सहित चार लोगों की मौत हो गई। हमले में कई लोग घायल हैं। शहबाज ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी और नागरिकों की हत्या पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनके परिवारों का समर्थन करेगी। आईएमएफ टीम की यात्रा के बाद, मंत्री और बिजली सचिव मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के लिए कश्मीरी अधिकारियों से बात करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को अपना नैतिक और राजनयिक समर्थन देना जारी रखेगा।

भारत सरकार से अपील- यूएन में उठाएं मुद्दा

पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने हाल ही में भारत सरकार से अपील की कि भारत पाकिस्तान के राजदूत को तलब करे और उनसे स्पष्टीकरण मांगे। मिर्जा ने एक वीडियो बयान जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि आज सुबह लगभग पांच लाख लोग मुजफ्फराबाद और आसपास के शहरों में बिजली बिलों पर करों, सब्सिडी में कटौती का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि कि सरकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भत्तों और विशेषाधिकारों को समाप्त करे। मिर्जा ने वैश्विक समर्थन के लिए आग्रह किया है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि संयुक्त राष्ट्र में पीओके का मुद्दा उठाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के राजदूत को तलब करे और उनसे पीओके में हो रही हिंसा पर जवाब मांगे। मिर्जा ने दावा किया पीओके में दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हमारी जान खतरे में है।

भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कर्नल काले को दी श्रद्धांजलि, आईडीएफ - यूएनडीएसएस के अफसर भी थे मौजूद

तेल अवीव । इजराइल में भारतीय दूतावास के दो अधिकारियों ने कर्नल वैभव अनिल काले को अंतिम सम्मान दिया। दरअसल, इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच गाजा में कर्नल काले की मौत हो गई। उनके शव को भारत वापस लाया गया। दूतावास के अधिकारियों के साथ इस्राइली विदेश मंत्रालय, इस्राइली सुरक्षाबल और संयुक्त राष्ट्र विभाग के बचाव और सुरक्षा (यूएनडीएसएस) अधिकारी बी शामिल हुए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा, इस्राइली विदेश मंत्रालय, आईडीएफ और यूएनडीएसएस अधिकारियों ने कर्नल वैभव काले के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने गाजा में अपनी जान गंवा दी। उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जा रहा है। यूएन में शामिल होने के लिए लिया था रिटायरमेंट राफा से खान यूनिस क्षेत्र में अस्पताल ले जाते समय 46 वर्षीय कर्नल काले की मौत हो गई थी।

अपने बच्चों को बड़े होते देखना काफी मजेदार : पद्मा लक्ष्मी

एक्ट्रेस ने टीनएजर बेटी कृष्णा के बारे में की बात

लॉस एंजेलिस । एक्ट्रेस पद्मा लक्ष्मी ने अपनी टीनएजर बेटी कृष्णा के बारे में बात की और बताया कि वह कुछ चीजों को लेकर पेरेंटिंग में काफी सख्त हैं। पद्मा सोशल मीडिया पर अपनी 14 वर्षीय बेटी कृष्णा की फोटो और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

पद्मा ने बताया, मुझे लगता है कि कोई भी माता-पिता यह अच्छे से समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हमने पहले से तैयारी की थी। हम बस सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे, ओह, वह फनी है। यह फनी है और तभी मैंने कहा, चलो इसे रिकॉर्ड करें। यह बस एक प्रयोग है। अपने बच्चों को बड़े होते और वे जो बनना चाहते हैं, उन्हें वह बनते देखना काफी मजेदार है। उन्होंने कहा कि वह कभी-कभी कृष्णा के दो टूक जवाबों से हैरान रह जाती हैं। उन्होंने कहा, विभिन्न चीजों पर उसकी अपनी राय है... मुझे नहीं लगता कि वह अधिकतर टीनएजर्स से अलग है, शायद वह उम्र से थोड़ा पहले समझदार हो गई है। पद्मा लक्ष्मी ने कहा, मैं कुछ चीजों को लेकर सख्त हूं और कुछ चीजों को लेकर उतनी सख्त नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए, जैसे कि सोने का समय... वह अभी 14 साल की है।

मैं यह सुनिश्चित करने के बारे में सख्त थी कि वह अपने जीवन के पहले चार-पांच साल में बहुत अच्छा खाना खाए और मैं वयस्कों के अनादर को बर्दाश्त नहीं करती। वह ऐसी (अनादर करने वाली) नहीं है, लेकिन इस मामले में हमारी एशियाई संस्कृति सामने आती है - घर में आने से पहले अपने जूते उतारने और बड़ों को अंकल या आंटी कहने जैसी हमारी परंपराओं का सम्मान।पद्मा ने बताया कि कृष्णा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखती हैं, लेकिन उनकी बेटी का अपना कोई अकाउंट नहीं है। उन्होंने कहा, वह सोशल मीडिया पर नहीं है, मुझे इसके बारे में पता है।

रूस ने ब्रिटेन के रक्षा अताशे को किया निष्कासित, एक सप्ताह में छोड़ना होगा देश

मॉस्को । रूस-यूक्रेन युद्ध को दो साल से भी अधिक समय हो गया है। इस दौरान मॉस्को और लंदन के बीच तनाव और तकरार बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन ने जासूसी के आरोपों पर इस महीने की शुरुआत में रूसी रक्षा अताशे को निष्कासित कर दिया था। वहीं अब रूस ने पलटवार करते हुए ब्रिटेन के रक्षा अताशे एड्रियन कॉघिल को मास्को से निष्कासित कर दिया है।

आठ मई को किया था ब्रिटेन पर वार

बता दें कि आठ मई को ब्रिटेन में रूस के रक्षा अताशे को निष्कासित कर दिया गया था, जिस पर जासूस होने का आरोप लगाया था और सीकॉक्स हीथ संपत्ति और रूसी दूतावास से राजनयिक दर्जा हटा दिया था। ब्रिटेन ने रूसी राजनयिक वीजा पर भी नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें राजनयिकों द्वारा देश में बिताए जाने वाले समय की अवधि भी शामिल है। रक्षा अताशे एड्रियन कॉघिल पर कार्रवाई मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटिश राजनयिक को सूचित किया गया कि मॉस्को में ब्रिटेन के दूतावास में रक्षा अताशे एड्रियन कॉघिल को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर रूस को छोड़ना होगा। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की रूस विरोधी कार्रवाइयों पर हमारी प्रतिक्रिया, जो आठ मई को घोषित की गई थी, इस उपाय तक सीमित नहीं है। तनाव भड़काने वालों को आगे के प्रतिक्रिया कदमों के बारे में सूचित किया जाएगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स ने कॉघिल को रूस से निष्कासित करने को हताशा भरा कदम बताया।

ब्रिटेन और रूस का संबंध

रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन का रूस के साथ वर्षों से असहज संबंध रहा है। वह अपने एजेंटों पर लक्षित हत्याओं और जासूसी का आरोप लगाता है, जिसमें ब्रिटिश सांसदों पर लक्षित साइबर हमले और रूसी हितों की सेवा के लिए संवेदनशील जानकारी को लीक करना और बढ़ाना शामिल है।

प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुआ हमला राजनीतिक नहीं; आंतरिक मंत्री ने किया ये दावा

ब्राटीस्लावा । स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुए हमले को लेकर वहां के आंतरिक मामलों के मंत्री मेटस सुटेज ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पीएम फिको की हत्या की कोशिश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने दावा किया था कि हमले की शुरुआती जांच में फीको पर हमले के पीछे पाया गया कि यह राजनीति से प्रेरित था। हालांकि, वे अपने पूर्व बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि जिस संदिग्ध पर हमले का आरोप लगाया गया है, उसका किसी भी राजनीतिक समूह से संबंध नहीं है। उसने अकेले ही इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि उन्होंने हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की। इसके साथ ही प्रधान मंत्री रॉबर्ट फिको पर हमला

करने वाले संदिग्ध पर पूर्व-निर्धारित हत्या का आरोप लगाया गया है। आंतरिक मामलों के मंत्री ने कहा कि इस हमले का वो अकेला मास्टरमाइंड है। बीते महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उसने हाल ही में सरकार विरोधी भावना व्यक्त की थी। इससे पहले, अस्पताल के एक अधिकारी ने फिको की हालत की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर थी। बता दें कि स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटीस्लावा के हैंडलोवा शहर में उन पर कई गोलियां बरसाई गई। उन पर हमला तब किया गया जब एक सरकारी मीटिंग के बाद फिको अपने समर्थकों से मिल रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने रॉबर्ट फिको को करीब से पांच गोलियां मार दी। वहीं प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने मौके से ही आरोपी हमलावर को पकड़ लिया, जिसकी पहचान जुराज सिनटुला (71 वर्षीय) के रूप में हुई है। आरोपी एक कवि है और बताया जा रहा है कि वह, रॉबर्ट फिको की नीतियों से नाराज था और इसी के चलते उसने फिको पर हमला किया। लोकलुभावन नेता को जान से मारने की इस कोशिश ने छोटे से देश को हिलाकर रख दिया है। यूरोपीय चुनावों से कुछ हफ्ते पहले पूरे महाद्वीप में इसकी गूंज सुनाई दी है।कई लोगों ने इस हमले के लिए आंशिक रूप से अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहराया है जिसने देश को विभाजित कर दिया है। कौन हैं रॉबर्ट फिको रॉबर्ट फिको का जन्म साल 1964 में हुआ और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत स्लोवाकिया की आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के तौर पर की। रॉबर्ट फिको के पास कानूनी की डिग्री है और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव है। स्लोवाकिया की राजनीति में रॉबर्ट फिको एक बड़ा नाम हैं। रॉबर्ट फिको ने साल 1992 में स्लोवाकिया की संसद का चुनाव लड़ा और साल 1999 में वह स्मेर (डायरेक्शन) पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे।

तानाशाह किम की बहन बोली- हमने रूस को हथियार नहीं दिए

नॉर्थ कोरिया के हथियार देश की रक्षा के लिए, बेचने के लिए नहीं

प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने रूस को हथियार देने के अमेरिका और साउथ कोरिया के दावों को गलत बताया है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी न्यूज चैनल के मुताबिक किम यो जोंग ने कहा कि रूस को हथियार देने की बातें मनगढ़ंत और बेतुकी हैं। किम यो जोंग ने कहा, नॉर्थ कोरिया ने देश की सुरक्षा के लिए हथियार बनाएं हैं, किसी दूसरे देश को बेचने के लिए नहीं।

किम की बहन का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका ने रूस की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएं है। इन पर नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हथियारों की डील कराने के आरोप थे। दरअसल, नॉर्थ कोरिया के हथियार खरीदने और बेचने पर (संयुक्त राष्ट्र संघ) ने पाबंदियां लगा रखी हैं।

अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार रूस पर नॉर्थ कोरिया से मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहायता के बदले में यूक्रेन युद्ध के लिए तोपखाने, मिसाइल और दूसरे हथियार खरीदने के आरोप लगाते रहे हैं।

दावा- नॉर्थ कोरिया ने हथियारों के 7 हजार कंटेनकर रूस भेजे

साउथ कोरिया ने मार्च में दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक रूस को हथियारों से भरे 7 हजार कंटेनर भेजे। इसके बदले नॉर्थ कोरिया में रूस के 9 हजार कंटेनर आए थे। इनमें खाने की कमी झेल रहे नॉर्थ कोरिया के लिए मदद का सामान होने का दावा किया गया।

वहीं, वॉशिंगटन में बैठे एक्सपर्ट्स का दावा है कि नॉर्थ कोरिया को हथियार भेजने के बदले सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मिली है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में कहा था कि वे अपनी सेना के लिए 240 मिलीमीटर के रॉकेट लॉन्चर बनाएगा, जो सेना की जंग लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे।

यूक्रेन में दागीं मिसाइलों से खुलासा

अमेरिका के साथ-साथ यूक्रेन का भी दावा है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदे हैं। जनवरी में रूस के खार्किव शहर में दागी गई एक मिसाइल के मलबे से इसकी पुष्टि होने का दावा किया गया। सिर्फ हथियार ही नहीं अमेरिका का दावा है कि रूस ने ह सिक्योरिटी कार्उसिल की लिमिट से आगे जाकर नॉर्थ कोरिया को रिफाइंड पेट्रोल दिया है।

1990 से खाने की कमी से जूझ रहा नॉर्थ कोरिया

रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 1990 के दशक में खतरनाक अकाल पड़ा था। तब से वहां पर खाने की कमी है। फरवरी 2023 में एक्सपर्ट्स ने चेताया था कि अनाज के उत्पादन में कमी होने की वजह से नॉर्थ कोरिया में खाने का संकट गहरा गया है। बेकार मौसम और अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते वहां स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। साउथ कोरिया की सैटलाइट इमेज से दिखाया था कि नॉर्थ कोरिया में साल 2022 में 2021 के मुकाबले 18 हजार टन कम अनाज पैदा हुआ था।

किम जोंग ने लोगों को कम खाना खाने का आदेश दिया था

2022 में उत्तर कोरिया से आई एक रिपोर्ट ने दावा किया था कि अनाज की कमी को पूरा करने के लिए किम जोंग उन ने लोगों से कम खाना खाने को कहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक, कोरिया वर्कर्स पार्टी की बैठक में किम जोंग ने कहा था- अब देश में फैक्ट्रियां लगाने पर काम होगा और लोगों के जीवन में सुधार लाया जाएगा।